

अनिश्चित समय में जीत: भारतीय अनुभव*

शक्तिकान्त दास

इस एफआईबीएसी सम्मेलन¹ में एक बार फिर मुझे आमंत्रित करने के लिए फिक्की और आईबीए का मैं आभारी हूँ। चूंकि वित्तीय और व्यावसायिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, इस तरह के आयोजन उद्योग जगत के नेताओं, बैंकों और नीति निर्माताओं को हमारे वर्तमान मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा भविष्य की दिशा तय करने में विचारों में स्पष्टता लाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। वर्तमान में दुनिया 2020 से चुनौतियों की एक अंतहीन शृंखला से जूझ रही है। भू-राजनीतिक संघर्ष, भू-आर्थिक विखंडन, अस्थिर वस्तु कीमतें, मौद्रिक नीतियों की भावी दिशा और उनके व्यापक-वित्तीय परिणामों में अनिश्चितता, जलवायु आघातों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता, इन सभी का एक साथ उत्पन्न होना अत्यंत जटिल स्वरूप की या यों कहिए कि जोखिम भरी कई चुनौतियों को खड़ा करते हैं। ऐतिहासिक नियमितताएँ अनिश्चित लग रही हैं और नीति निर्माताओं को कसौटी से गुजरना पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में, आज के सम्मेलन का विषय - "अनिश्चित समय में जीत" - सभी बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद प्रगति करने की मानवता की लंबे समय से चली आ रही कोशिश का प्रतिनिधित्व करना है। मैं आशावादी हूँ और मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर प्रयास कर सकते हैं और इस अस्थिर दौर से निपट सकते हैं।

सम्मेलन के विषय के अनुरूप मैं व्यापक रूप से आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में पिछले डेढ़ वर्षों में रिज़र्व बैंक की नीतियों और कार्यों पर बात करना चाहूँगा। इसके बाद मैं भारत के संवृद्धि चालकों और उभरते अवसरों के बारे में बात करूँगा जिनका उपयोग भारत की संभावित संवृद्धि को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अंत में मैं कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जिन पर बैंकों, एनबीएफसी, वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं और यहां तक कि कारोबारियों का भी ध्यान जाना चाहिए।

* मुंबई में फिक्की और आईबीए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एफआईबीएसी 2023 सम्मेलन में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण - 22 नवंबर 2023।

¹ फेडरेशन ऑफ इंडियन बैंक्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए)।

बीते वर्ष में मौद्रिक नीति का संचालन

पिछले डेढ़ वर्षों में रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति कार्रवाइयों में संवृद्धि की तुलना में मुद्रास्फीति को प्राथमिकता देना, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) गलियारे को कम करना, नीतिगत रेपो दर को 250 बीपीएस तक बढ़ाना और अतिरिक्त चलनिधि को समाप्त करना शामिल है। इसके अलावा सरकार ने भी आपूर्ति पक्ष के उपाय किए। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2023 में हेडलाइन मुद्रास्फीति को 4.9 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिली। इसके अलावा कोर मुद्रास्फीति में आई कमी विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

हाल ही में इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि घरेलू मुद्रास्फीति की उम्मीदें और अधिक स्थिर हो गई हैं² तथापि, हेडलाइन मुद्रास्फीति, वैश्विक कारकों और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले आवर्ती और अतिव्यापी खाद्य मूल्य आघातों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। हाल के समय में ऐसे आघातों की संख्या बढ़ी है और उनकी तीव्रता में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति को संवृद्धि का समर्थन करते हुए सतर्क रहने और सक्रिय रूप से मुद्रास्फीति को कम रखने की आवश्यकता है।

मुझे यह अवश्य साझा करना चाहिए कि पिछले डेढ़ वर्षों में हमारे कार्यों की वजह से वित्तीय स्थिरता के लिए कोई जोखिम पैदा नहीं हुआ, जैसा कि 2023 की शुरुआत में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया था। इसका श्रेय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक आवश्यकताओं, जिनका बैंकों द्वारा अपने ब्याज दर जोखिम को प्रबंधित करने के लिए अनुसरण किया जाना अपेक्षित है, को दिया जा सकता है। ये आवश्यकताएं भविष्य के ऐसे दबाव के लिए सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करती हैं जो ब्याज दर चक्र के विपरीत दिशा में जाने पर उत्पन्न हो सकते हैं³

² सितंबर 2022 से घरेलू मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रण में रखा जा रहा है। तीन महीनों के लिए मुद्रास्फीति की उम्मीदें 10.0 प्रतिशत (जुलाई 2023 दौर) से 90 बीपीएस गिरकर 9.1 प्रतिशत (सितंबर 2023 दौर) हो गईं और 10.3 प्रतिशत (जुलाई 2023 दौर) से एक साल आगे के लिए 40 बीपीएस गिर कर 9.9 प्रतिशत (सितंबर 2023 दौर) हो गईं।

³ भारत में पूंजी और चलनिधि की अनिवार्यता सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उनकी आस्तिका आकार और जोखिम कुछ भी हो। बैंकों में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) भी गठित की गई है। बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी के निवेश पर मूल्यांकन दिशानिर्देश सख्त हैं और रूढ़िवादी दृष्टिकोण का पालन करते हैं।

विनिमय दर की बात करें तो अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर में आयी मजबूती के बावजूद भारतीय रुपये (आईएनआर) में समकक्ष देशों की तुलना में अस्थिरता कम रही और स्थिति के अनुरूप उसका उतार-चढ़ाव रहा।⁴ आईएनआर में उतार-चढ़ाव उपलब्ध समष्टि-आधार व्यवस्था की मजबूती और बफर्स की भरोसेमंद उपलब्धता के अनुरूप है।

संवृद्धि के चालक और अवसर

चूंकि यहां व्यापार जगत के कई शीर्ष कारोबारी मौजूद हैं, मैं भारत के संवृद्धि चालकों और आगे आने वाले अवसरों पर बात करना चाहूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2020-21 में 5.8 प्रतिशत के कोविड-प्रेरित संकुचन से जोरदार वापसी की और 2021-22 में 9.1 प्रतिशत और 2022-23 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। भारत की वास्तविक जीडीपी 2023-24 और 2024-25 दोनों में 6.5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगी।⁵ दरअसल, भारत क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में पहले से ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक मंदी के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था समुत्थानशील बनी हुई है और घरेलू मांग पर अधिक निर्भरता के कारण इसका विकास जारी है, और इसी ने अर्थव्यवस्था को कई वैश्विक प्रतिकूलताओं का सामना करने में सक्षम बनाया है। यद्यपि भारत ने व्यापार और वित्तीय मार्गों के माध्यम से बाहरी जगत के साथ आदान-प्रदान में तेजी से प्रगति की है और प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल की है, फिर भी घरेलू मांग पर इसकी निर्भरता बाहरी आघातों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग, कराधान, मुद्रास्फीति प्रबंधन और विनिर्माण

क्षेत्र आदि में लागू किए गए विभिन्न संरचनात्मक सुधारों ने टिकाऊ और उच्च संवृद्धि की नींव रखी है।

हम दोहरे घाटे और दोहरे तुलन-पत्र दबाव के युग से दोहरे तुलन-पत्र लाभ के वर्तमान समय में पहुंच गए हैं।⁶ एक ओर आर्स्टि गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार के कारण बैंकों के तुलनपत्रों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, वहीं कॉरपोरेट भी अपने तुलनपत्रों का भार कम करते हुए मजबूत वित्तीय प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंकों और कॉरपोरेट्स की बेहतर स्थिति उनके 2023-24 की हालिया दूसरी तिमाही के नतीजों में भी झलकती है। 1501 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों पर आधारित कॉरपोरेट प्रदर्शन मानदंड 2023-24 की दूसरी तिमाही में लाभप्रदता और कर्मचारियों की लागत में मजबूत वृद्धि का संकेत देते हैं। रिज़र्व बैंक के नवीनतम औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि 2023-24 की तीसरी तिमाही में विनिर्माण कंपनियों की मांग की स्थिति के बारे में आशावादी होने से व्यावसायिक संभावनाओं में और सुधार हुआ है। मौसमी रूप से समायोजित आधार पर विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) में वृद्धि जारी है जो निवेश गतिविधि के लिए अच्छा संकेत है। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर भी निवेश गतिविधि के लिए अनुकूल है। अब यह कॉरपोरेट्स और अन्य व्यवसायों पर निर्भर है कि वे भारत की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करें और आगे बढ़ें।

आपूर्ति पक्ष पर गौर करें तो कृषि क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छी प्रगति बनाए रखी है। असमान दक्षिण-पश्चिम मानसून और खरीफ उत्पादन कम रहने के बावजूद 2023-24 के दौरान इसका प्रदर्शन स्थिर रहने की उम्मीद है। खाद्यान्नों के साथ-साथ बागवानी का उत्पादन भी साल दर साल उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उत्पादों और गंतव्यों, दोनों के संदर्भ में निर्यात के विविधीकरण के चलते अर्थव्यवस्था की आघात झेलने की क्षमता बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र अभी भी हमारे कार्यबल के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान कर रहा है।

⁴ 20 नवंबर 2023 तक, डॉलर के मुकाबले आईएनआर में (कैलेंडर वर्ष के आधार पर) 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी, किंतु वह चीनी युआन, थाईलैंड के बाह्त, वियतनामी डॉंग, अर्जेंटीना के पेसो और मलेशियाई रिंगिट सहित समकक्ष ईएमई की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। जापानी येन के मुकाबले इसमें 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि यूरो के मुकाबले इसमें 2.7 प्रतिशत और यूके पाउंड के मुकाबले 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

⁵ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, भारत 2030 से पहले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अनुमान है कि भारत की जीडीपी क्रमशः 2026 और 2027 तक जापान और जर्मनी दोनों को पार कर जाएगी। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्रय शक्ति समता (पीपीपी) (वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ) के मामले में भारत पहले से ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है (स्रोत: आईएमएफ, विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) डेटाबेस)।

⁶ दोहरा घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई अर्थव्यवस्था राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटे दोनों से पीड़ित होती है। दोहरा तुलनपत्र दबाव एक ऐसा परिदृश्य है जहां बैंक गंभीर दबाव में होते हैं और कॉरपोरेट्स इस हद तक अधिक दबाव में होते हैं कि वे अपने ऋण चुका सकने की स्थिति में नहीं होते।

इन सभी के बावजूद, उत्पादकता अंतराल, जल के उपयोग और सिंचाई सुविधा, उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव और मौसम की आकस्मिक घटनाओं से संबंधित कई चुनौतियाँ हैं। इन सभी के लिए कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और इसकी वास्तविक क्षमता का उपयोग करने के लिए बुनियादी ढांचे और नवाचार में भारी निवेश की आवश्यकता है जिससे कि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके; बाजारों तक अधिक कुशल पहुंच बनाई जा सके; किसानों की आय बढ़ाई जा सके; और सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान बढ़ सके। एक राष्ट्र के रूप में हमें विशेष रूप से कृषि विपणन और संबंधित मूल्य शृंखलाओं के क्षेत्र में कुछ सुधार करने का रास्ता खोजना होगा। ये सुधार न केवल स्थायी उच्च संवृद्धि के लिए बल्कि टिकाऊ मूल्य स्थिरता के लिए और खाद्य मूल्य आघातों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र बड़े पैमाने पर आगे आये और इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार बने। निजी क्षेत्र के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश करने के अवसर हैं, जैसे कि आपूर्ति शृंखला; विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों और खाद्यान्नों से युक्त खाद्य प्रसंस्करण; डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य व्यवसाय वर्धन; और विपणन संरचना निर्माण। निजी क्षेत्र फार्म-फर्म (अर्थात्, कृषि-उद्योग) सहबद्धता में तेजी ला सकता है और अंतिम ग्राहक तक संपूर्ण मूल्य शृंखला की दक्षता में सुधार कर सकता है।

जहां तक विनिर्माण क्षेत्र का सवाल है, भले ही पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी लगभग 17-18 प्रतिशत रही है, इसमें संवृद्धि और रोजगार में अपने योगदान को बढ़ाने की क्षमता है। अपनी युवा श्रम शक्ति के साथ भारत का जनसांख्यिकीय लाभ वैश्विक विनिर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का एक अनूठा अवसर भी उपलब्ध कराता है। हमारे लिए वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का हिस्सा बनना महत्वपूर्ण है जो एक खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनर्गठन के दौर से गुजर रही हैं। उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी पहल हमारे सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अनुकूल स्थितियां बनाती हैं। स्मार्ट फोन, बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों ने

पीएलआई योजना के तहत अच्छा निष्पादन दर्ज किया है। एयरोस्पेस और रक्षा, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहनों और अर्धचालक जैसे उभरते क्षेत्रों में भी बड़ी संभावनाएं हैं। मजबूत सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में हमारे प्रयास, जो डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और सभी क्षेत्रों में लेनदेन को सुलभ बना रहे हैं, प्रौद्योगिकी अपनाने और उत्पादकता को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करते रहेंगे।

वर्तमान में सेवा क्षेत्र का भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है और वह समग्र संवृद्धि का आधार बना हुआ है। भारतीय सेवा क्षेत्र सेवा वितरण, पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकों को तेजी से अपना रहा है। नए उभरते स्टार्ट-अप भी बड़े पैमाने पर सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। कम कौशल वाली उपभोक्ता-उन्मुख सेवाओं से अधिक प्रौद्योगिकी-सक्षम व्यावसायिक सेवाओं की ओर लगातार संक्रमण हो रहा है। यह स्थिति, वास्तव में भारतीय व्यवसायों के लिए इस अंतर्निहित धारा को पहचानने और इस क्षेत्र में बाहरी मांग को पूरा करने के लिए अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए एक अवसर है।

दरअसल, हमारे सेवा निर्यात की क्षमता के कारण बाह्य व्यापार के मामले में भारत की स्थिति मजबूत है, जो काफी हद तक समुत्थानशील बनी हुई है। सेवा निर्यात ने भारत के चालू खाता घाटे को सहारा दिया है, जबकि वैश्विक मांग कमजोर होने के कारण व्यापारिक निर्यात दबाव में रहा है। चालू खाता घाटा और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात लगभग 10 वर्षों से 2 प्रतिशत से नीचे बना हुआ है। भारत का सेवा निर्यात सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित सेवाओं से लेकर व्यवसाय विकास, अनुसंधान और विकास, पेशेवर प्रबंधन, लेखा और कानूनी सेवाओं जैसी अन्य व्यावसायिक सेवाओं तक वैविध्यपूर्ण हो रहा है।

कुल मिलाकर, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी और घरेलू मांग पर निर्भरता के साथ भारत की संवृद्धि यात्रा आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर हो सकती है।

वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर कुछ विचार

अब वित्तीय क्षेत्र के बारे में कुछ बात करते हैं। चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक सतत बदलते और अनिश्चित वैश्विक माहौल में बढ़ने का प्रयास कर रही है, इसलिए यह जरूरी है कि हमारा वित्तीय क्षेत्र मजबूत बना रहे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली बेहतर पूंजी अनुपात, आर्स्ति गुणवत्ता और मजबूत आय वृद्धि के कारण समुत्थानशील बनी हुई है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के वित्तीय संकेतक भी बैंकिंग प्रणाली के अनुरूप हैं। हालाँकि बैंक और एनबीएफसी अब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता है। अच्छे समय में, जैसा कि अब है, बैंकों और एनबीएफसी को इस बात पर विचार करने और आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि संभावित जोखिम कहां से उत्पन्न हो सकते हैं। यह ऐसा समय है जब उन्हें चाहिए कि वे अपनी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को और मजबूत करें और प्रतिकूल व्यापार चक्र की स्थिति का सामना करने के लिए अतिरिक्त बफर बनाएं।

हमारी ओर से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में बैंकों, एनबीएफसी और अन्य विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण को काफी मजबूत किया है। हमने हाल ही में स्थिरता बनाए रखने के लिए कुछ व्यापक विवेकपूर्ण उपायों की भी घोषणा की है। ये उपाय पूर्व-निवारक स्वरूप के हैं। वे सुविचारित और लक्षित हैं। इस बात पर गौर करना प्रासंगिक है कि आवास, वाहन और एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण जैसे प्रमुख संवृद्धि चालकों को इन उपायों से बाहर रखा गया है। हमने अभिशासन और आश्वासन कार्यों को मजबूत करने, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और ऋण देने की प्रथाओं के सुदृढीकरण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। हम अपने सक्रिय और दूरदर्शी पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के भाग के रूप में विभिन्न ऑनसाइट और ऑफसाइट साधनों, दबाव परीक्षण, संवेदनशीलता आकलन, विषयगत अध्ययन, डेटा डंप विश्लेषण इत्यादि के माध्यम से पर्यवेक्षित संस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपने बही-खातों का दबाव परीक्षण करते रहना चाहिए। स्थावर क्षेत्र की कंपनियों को भी चाहिए कि वे अपने व्यवसाय और तुलन-पत्र का परीक्षण करने पर जोर दें। उनमें से कई पहले से ही ऐसा कर रही होंगी, लेकिन यह अच्छा होगा कि अन्य भी ऐसा करें।

वर्तमान में चिंता का कोई तात्कालिक कारण नहीं है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बैंकों और एनबीएफसी को कुछ एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी जाती है। इस सन्दर्भ में मैं चार बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

पहला, जबकि वर्तमान में ऋण वृद्धि में तेजी आ रही है, बैंक और एनबीएफसी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें कि समग्र, क्षेत्रवार और उप-क्षेत्रवार स्तरों पर ऋण वृद्धि टिकाऊ बनी रहे और किसी भी प्रकार के अतिउत्साह से बचा जाए। क्रेडिट पोर्टफोलियो का विस्तार और उसका मूल्य निर्धारण परिकल्पित जोखिमों के अनुरूप होना चाहिए। बैंकों और एनबीएफसी को भी अपने आर्स्ति देनदारी प्रबंधन को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्हें अपनी देनदारी पक्ष पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कुछ मामलों में हमने उच्च लागत वाले अल्पकालिक थोक जमा पर बढ़ती निर्भरता देखी है, जबकि खुदरा और कॉर्पोरेट ऋण, दोनों में ऋण की अवधि बढ़ रही है।

दूसरा, वित्तीय प्रणाली में गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बढ़ते महत्व⁷ को देखते हुए, बैंकों और गैर-बैंकों के बीच बढ़ते अंतर्संबंध पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एनबीएफसी वित्तीय प्रणाली से निधि लेने वाले बड़े शुद्ध उधारकर्ता हैं तथा बैंकों के साथ उनका एक्सपोजर सबसे अधिक है। उधार बैंक भी एनबीएफसी द्वारा जारी डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों के प्रमुख ग्राहकों में से एक हैं। एनबीएफसी एक साथ कई बैंकों से उधार लेती हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के संकेंद्रित संबंध संक्रामक जोखिम पैदा कर सकते हैं। हालाँकि बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं, फिर भी उन्हें एनबीएफसी के प्रति अपने एक्सपोजर और व्यक्तिगत एनबीएफसी के कई बैंकों के प्रति एक्सपोजर का लगातार मूल्यांकन करना चाहिए। एनबीएफसी को अपनी ओर से अपने निधि प्राप्त करने के स्रोतों को व्यापक बनाना चाहिए और बैंक निधि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

तीसरा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म वित्त एक महत्वपूर्ण वित्तीय माध्यम के रूप में उभरा है। चूँकि

⁷ एनबीएफसी की व्यापक उपस्थिति उनके बढ़ते क्रेडिट-जीडीपी अनुपात में परिलक्षित होती है जो 2012-13 और 2021-22 के बीच 8.6 प्रतिशत से 12.3 प्रतिशत तक पहुंचा है।

सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) हाशिए पर रहने वाले ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं, इसलिए उन्हें उधारकर्ताओं की सामर्थ्य और पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखना होगा। यद्यपि ब्याज दरों को विनियमन से मुक्त कर दिया गया है, फिर भी कुछ एनबीएफसी-एमएफआई अपेक्षाकृत उच्च शुद्ध ब्याज मार्जिन का लाभ ले रहे हैं। यह सूक्ष्म वित्त उधारदाताओं पर है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ब्याज दरें निर्धारित करते समय वे उन्हें प्रदान किए गए लचीलेपन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करें। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी ब्याज दरें पारदर्शी रखें और वे सूदखोरी प्रवृत्ति के न हों।

चौथा, फिनटेक के साथ बैंकों और एनबीएफसी के बढ़ते सहयोग से अभिनव उत्पादों और सेवाओं तथा नए व्यापार मॉडल की शुरुआत संभव हो रही है। डिजिटल प्रौद्योगिकियां बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम प्रदान कर रही हैं। इससे परिचालन लागत में भी कमी आई है और वित्तीय सेवा प्रदाताओं की पहुंच को बढ़ाने में मदद मिली है। एक महत्वपूर्ण पहलू जो इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है, वह एनालिटिक्स के माध्यम से मॉडल-आधारित ऋण देने के संबंध में है। बैंकों और एनबीएफसी को केवल पूर्व-निर्धारित एल्गोरिदम, जिसके आधार पर मॉडल संचालित होते हैं, पर भरोसा करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन मॉडलों का सुदृढ़ होना आवश्यक है और समय-समय पर उनकी जांच और पुनः जांच की जानी चाहिए। वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के बदलते स्वरूप और

नई जानकारी के आधार पर समय-समय पर उन्हें कैलिब्रेट और पुनः कैलिब्रेट करने की आवश्यकता हो सकती है। इन मॉडलों में सूचना अंतराल के कारण प्रणाली में उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी अनुचित जोखिम के प्रति सावधान रहना आवश्यक है, जो मूल मानकों को कमजोर करने का कारण बन सकती है।

निष्कर्ष

हम एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में अत्यधिक अनिश्चित समय में रह रहे हैं। समय-समय पर नये-नये खतरे सामने आते रहते हैं। जोखिम के नये स्रोत भी सामने आ रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में, समुत्थाशीलता को और बढ़ाना आघातों और अनिश्चितताओं का मुकाबला करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होगा। यह सभी व्यवसायों और वित्तीय संस्थाओं के भी हित में है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यहां बैंकिंग और कॉरपोरेट जगत के कई मान्यवर उपस्थित हैं, इसलिए मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ कि नए अवसर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। यह हमारा काम है कि हम उनका लाभ उठाएं। क्षमता निर्माण में निवेश, मानव संसाधनों को कुशल बनाने और सभी सहभागियों द्वारा नई तकनीक को अपनाने पर अधिक ध्यान देना होगा। भारत की संभावनाओं पर अंतरराष्ट्रीय विश्वास नई ऊंचाई पर है; यह भारत के लिए एक उपयुक्त अवसर है और मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास की दिशा में काम करने का यह एक उपयुक्त समय है।

धन्यवाद, नमस्कार!